उत्तर प्रदेश
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

ई-संदेश

04 अगस्त 2021, वर्ष 4, अंक 149

सात दिन – सात पृष्ठ

गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को मीरजापुर में 'माँ विन्ध्य कॉरिडोर' परियोजना के निर्माण का भूमि पूजन व शिलान्यास के मौके पर स्मृति चिन्ह प्रदान करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

★ एविएशन सेक्टर आज के समय में बहुआयामी प्रगति का द्योतक है, इससे आर्थिक विकास में गुणोत्तर वृद्धि होती है

★ स्थानीय समस्याओं का समाधान तहसील, थाना व जनपद स्तर पर ही किया जाए

★ प्रधानमंत्री की प्रेरणा से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है

★ प्रदेश के थानों में महिला पुलिसकर्मियों को बीट इंचार्ज बनाया जाए

★ प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप यूपी में कानून का राज स्थापित हुआ

★ मीडिया समाज के सजग प्रहरी के रूप में सरकार का ध्यान ज्वलन्त मुद्दों की ओर दिलाता है

★ वर्तमान सरकार ने सवा चार वर्षों के दौरान निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया

★ कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

कोरोना हारेगा भारत जीतेगा

एविएशन सेक्टर आज के समय में बहुआयामी प्रगति का द्योतक है, इससे आर्थिक विकास में गुणोत्तर वृद्धि होती है : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु आज 1,334 हेक्टेयर भूमि के कब्जा हस्तांतरण मेमोरेण्डम पर हस्ताक्षर किए गए। 'ज्युरिख एयरपोर्ट इण्टरनेशनल एजी' की तरफ से सीईओ क्रिसटोफ शेलमन, किरन जैन और लीगल हेड शोभित गुप्ता तथा नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से निदेशक नागरिक उड्डयन विशाख जी, यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सीईओ डा अरुण वीर सिंह और नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने हस्ताक्षर किये।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एविएशन सेक्टर आज के समय में बहुआयामी प्रगति का द्योतक है, इससे आर्थिक विकास में गुणोत्तर वृद्धि होती है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में पीपीपी मोड पर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास की योजना परिकल्पित की गयी। राज्य सरकार के इस प्रयास में केन्द्र सरकार का निरन्तर भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट की स्थापना से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक अवस्थापना का विकास होगा, जिससे रोजगार एवं निवेश के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा, विनिर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहन मिलने के साथ–साथ हवाई यातायात सुगम होगा। इस परियोजना से पर्यटन के क्षेत्र में भी अप्रत्याशित वृद्धि होने की सम्भावना है। जेवर एयरपोर्ट की स्थापना से कई लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।

ज्ञातव्य है कि जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास के लिए नागर विमानन मंत्रालय में साइट क्लीयरेंस व इन–प्रिंसिपल अप्रूवल तथा रक्षा मंत्रालय की अनापत्ति हेतु आवेदन किया गया। नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार से 06 जुलाई, 2017 को साइट क्लीयरेंस तथा 09 मई, 2018 को इन–प्रिंसिपल अप्रूवल प्राप्त हुआ। जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास हेतु 08 नवम्बर, 2017 को गृह मंत्रालय से इमीग्रेशन सर्विसेज हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ।

05 अक्टूबर, 2017 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार से एमएचए क्लीयरेंस प्राप्त हुआ तथा 11 जनवरी, 2018 को रक्षा मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी। जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास की परियोजना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से 09 मार्च, 2020 को पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त हुआ। एयरपोर्ट की स्थापना हेतु लगभग 4,100 करोड़ रुपये की लागत से 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013' में विहित व्यवस्था के अनुसार, 1,334 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। एयरपोर्ट की भूमि से सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक 48.0970 हे भूमि का अधिग्रहण भी पूर्ण किया जा चुका है।

कार्यदायी संस्था यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकास सम्बन्धी कार्यों का ई–टेण्डर कर, स्थल पर विकास कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। एयरपोर्ट के विकास हेतु ग्लोबल ई–टेण्डर के माध्यम से, सबसे अधिक प्रति पैसेन्जर राजस्व की बोली (400.97 रुपये) लगाने वाली कम्पनी 'ज्युरिख एयरपोर्ट इण्टरनेशनल एजी' को विकासकर्ता के रूप में चयनित किया गया है।

जेवर एयरपोर्ट के लिए चयनित विकासकर्ता 'ज्युरिख एयरपोर्ट इण्टरनेशनल एजी' द्वारा गठित एसपीवी यमुना इण्टरनेशनल एयरपोर्ट प्रा लि एवं उत्तर प्रदेश सरकार की कम्पनी नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लि के साथ 07 अक्टूबर, 2020 को कन्सेशन एग्रीमेण्ट हस्ताक्षरित किया जा चुका है। यमुना इण्टरनेशनल एयरपोर्ट प्रा लि, नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लि एवं राज्य सरकार के मध्य त्रिपक्षीय स्टेट सपोर्ट एग्रीमेण्ट 01 मार्च, 2021 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है। यमुना इण्टरनेशनल एयरपोर्ट प्रा लि एवं नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लि के मध्य 17 जुलाई, 2021 को शेयर होल्डर एग्रीमेण्ट भी निष्पादित किया जा चुका है।

स्थानीय समस्याओं का समाधान तहसील, थाना व जनपद स्तर पर ही किया जाए : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा है कि जनता से जुड़ी समस्याओं व शिकायतों का समाधान सम्बन्धित व्यक्ति की संतुष्टि के आधार पर ही माना जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय समस्याओं का समाधान तहसील, थाना व जनपद स्तर पर ही किया जाए, जिससे जनता को समस्याओं के समाधान के लिए लखनऊ की दौड़ न लगानी पड़े। उन्होंने जनपद स्तर पर अधिकारियों को हर हाल में प्रतिदिन जनसुनवाई सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों सहित वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने आईजीआरएस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, एल्डर हेल्पलाइन, थाना व तहसील दिवस, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, गो–आश्रय स्थल, कानून–व्यवस्था, कोविड–19 आदि विषयों पर अधिकारियों से संवाद किया और उन्हें आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक माह के 02 शनिवार थाना दिवस तथा 02 शनिवार तहसील दिवस के लिए निर्धारित किये गये हैं। इन दिवसों में जनता की शिकायतों व समस्याओं के सम्बन्ध में निरन्तर समीक्षा करते हुए त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए एल्डर हेल्पलाइन बनायी गयी है। इस प्रकार की हेल्पलाइन का कार्य प्रत्येक जनपद में किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी के सहयोग से कोविड–19 की स्थिति नियंत्रित हुई है, किन्तु अभी भी सावधानी और सतर्कता प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी आयोजनों व कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। कोविड वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि इसकी दूसरी डोज के प्रति लापरवाही व ढिलाई न हो। उन्होंने निगरानी समितियों द्वारा इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर (आईसीसीसी) के साथ समन्वय कर निरन्तर कार्य किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईसीसीसी का उपयोग कोविड सम्बन्धी समस्याओं के समाधान, स्वच्छता व सैनिटाइजेशन, वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान आदि के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि बरसात के दृष्टिगत बाढ़ के नियंत्रण एवं बचाव के सभी प्रबन्ध व तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी को प्राप्त हो। इसके दृष्टिगत व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। प्रत्येक उचित दर की दुकान पर आगामी 05 अगस्त को कम से कम 100 लाभार्थियों को उपलब्ध कराए गये बैग में खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक सरकारी राशन की दुकान के लिए नोडल अधिकारी तैनात किये जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 09 अगस्त को अगस्त क्रांति व काकोरी की घटना के दृष्टिगत प्रदेश के शहीद स्मारकों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। पुलिस व सुरक्षा बलों के बैण्ड वादन सहित देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। शहीद के परिजनों को सम्मानित किया जाए। उन्होंने कहा कि गो–आश्रय स्थल के सम्बन्ध में शिकायतें न प्राप्त हों। वहां पर जल जमाव न हो। प्रत्येक गौशाला के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती हो। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गो–आश्रय स्थलों की सुचारू व्यवस्था हेतु निरीक्षण किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेन्स की नीति है। महिलाओं व बालिकाओं तथा कमजोर वर्गों के प्रति अपराधिक घटनाओं पर हर हाल में शीघ्रता से कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के अच्छे परिणाम आए हैं। इस अभियान को अन्तर्विभागीय समन्वय से और बेहतर ढंग से संचालित किया जाए। पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की व्यवस्था और सुदृढ़ हो। पीआरवी–112 का बेहतर व प्रभावी संचालन किया जाए।

प्रधानमंत्री की प्रेरणा से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है : मुख्यमंत्री

गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में जनपद मीरजापुर में 'मां विन्ध्य कॉरिडोर' परियोजना के निर्माण का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। तदुपरान्त जनपद के राजकीय इण्टर कॉलेज के मैदान में गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार ने मां विन्ध्यवासिनी कॉरिडोर व दर्शनार्थियोंध्पर्यटकों के विन्ध्याचल त्रिकोण दर्शन में सुगमता हेतु अष्टभुजा एवं काली खोह में 16.40 करोड़ रुपये की लागत से रोप–वे का लोकार्पण किया। गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार तथा मुख्यमंत्री ने मां विन्ध्यवासिनी देवी का दर्शन–पूजन भी किया।

इस अवसर पर गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के चहुंमुखी विकास के क्रम में मुझे उत्तर प्रदेश आने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार के कुशल नेतृत्व एवं प्रबन्धन में प्रयागराज में कुम्भ का दिव्य एवं भव्य आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। प्रदेश सरकार ने ब्रज तीर्थ एवं चित्रकूट धाम में विकास के साथ–साथ अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम द्वारा जनभावनाओं का आदर करते हुए अपनी परम्पराओं को विकसित किया है। सभी तीर्थ क्षेत्रों में जन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मां विन्ध्यवासिनी कॉरिडोर का शुभारम्भ एवं रोप–वे का उद्घाटन किया गया है। कॉरिडोर परियोजन में मंदिर परकोटा एवं परिक्रमा पथ का निर्माण, रोड व मेन गेट की अवस्थापना का निर्माण, मंदिर की गलियों में फसाड ट्रीटमेंट का निर्माण, पहुंच मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण कार्य, पार्किंग स्थल, शॉपिंग सेण्टर व अन्य यात्री सुविधाओं का निर्माण सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा रोप–वे का निर्माण किया है, जिससे अब किसी श्रवण को कांवड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के सभी बड़े बुजुर्ग दर्शनार्थियों को रोप–वे से बड़ी सुविधा प्राप्त होगी।

अमित शाह ने कहा कि सरकार ने गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए हैं। कोविड कालखण्ड में लोगों के जीवन एवं जीविका को बचाने के सफल प्रयास किए गए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में देशव्यापी निःशुल्क कोविड टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 05 किलो अनाज निःशुल्क वितरित किया जा रहा है।

शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अपने प्रत्येक वादे को पूरा किया है। आज उत्तर प्रदेश का बजट बढ़कर 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ रुपये हो गया है। विकास की गंगा पूरे प्रदेश में बहायी जा रही है। योगी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है और नरेन्द्र मोदी देश को 05 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कृतसंकल्पित हैं। आज उत्तर प्रदेश 44 केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है। योगी की मेहनत, सूझबूझ, प्रशासनिक क्षमता एवं उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरोना पर सफलतापूर्वक नियंत्रण एवं प्रबन्धन किया है। उत्तर प्रदेश कोविड टीकाकरण एवं टेस्टिंग में पूरे देश में अव्वल स्थान पर है।

प्रदेश में 01 लाख 80 हजार नये कोविड बेड उपलब्ध कराए गए हैं। 541 ऑक्सीजन प्लाण्ट बनाने का काम चल रहा है, जिनमें से 194 ऑक्सीजन प्लाण्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। छोटे बच्चों को निःशुल्क मेडिसिन किट उपलब्ध करायी जा रही है। निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए 'उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' की शुरुआत की गई है।

शाह ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निरन्तर आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है। आज प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है।

प्रदेश के थानों में महिला पुलिसकर्मियों को बीट इंचार्ज बनाया जाए : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित 'मिशन शक्ति अभियान' का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए समाज और जागरूक हो रहा है। महिला स्वावलम्बन की दिशा में क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि मिशन शक्ति को और गति प्रदान की जाए।

मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर मिशन शक्ति की अब तक की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर उनके समक्ष मिशन शक्ति के तृतीय चरण को लागू किये जाने के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतीकरण किया गया।

मुख्यमंत्री ने '1090' विमेन पावर लाइन पर दर्ज होने वाली शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी लेते हुए कहा कि इनका प्रभावी निस्तारण शिकायतकर्ता महिलाध्बालिका की संतुष्टि के अनुरूप किया जाए। साथ ही, उससे नियमित अन्तराल पर फीडबैक भी लिया जाए। उन्होंने प्रदेश के थानों में महिला पुलिसकर्मियों को बीट इंचार्ज बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए महिला सिपाहियों की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने महिलाओं की सहायता के लिए थानों में स्थापित की गई हेल्पडेस्क को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी समस्या लेकर थाने आने वाली महिलाओंध्बालिकाओं को वहां स्थापित महिला हेल्पडेस्क के माध्यम से पूरी मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने मिशन शक्ति के लिए महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को सक्रिय एवं प्रभावी सहयोग देने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख सचिव महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग हेकाली झिमोमी से विभाग द्वारा मिशन शक्ति तथा महिला सशक्तीकरण के सम्बन्ध में किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में सीसीटीवी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अतः अब तक स्थापित किये गये सभी सीसीटीवी को प्रभावी बनाते हुए इन्हें आपस में लिंक किया जाए। साथ ही, निजी क्षेत्र के आस्थानों, मॉल्स, कार्यालयों इत्यादि में स्थापित सीसी कैमरों को भी जोड़ा जाए। इसके लिए प्राइवेट सीसी कैमरा मालिकों का सहयोग प्राप्त किया जाए। उन्होंने सड़कों पर समुचित मार्ग प्रकाश की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गृह विभाग मिशन शक्ति का नोडल विभाग होगा और प्रत्येक स्तर पर मिशन शक्ति के क्रियान्वयन की समीक्षा यही विभाग करेगा।

मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के सम्बन्ध में किये गये प्रस्तुतीकरण को देखने के उपरान्त इस अभियान में जोड़े गए विभागों की संख्या को 05 से 07 तक सीमित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर विकास, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग जैसे प्रमुख विभागों को ही मिशन शक्ति में शामिल किया जाए। मिशन शक्ति की सफलता के लिए यह सभी विभाग अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए कुशलता से अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

मुख्यमंत्री के समक्ष मिशन शक्ति के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नीरा रावत ने इस अभियान के प्रतिभागी विभागों, मिशन के तहत भविष्य में किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तथा विभागवार कार्ययोजना के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मिशन से जुड़े विभागों के लिए साप्ताहिक योजना के निर्धारण के साथ–साथ सम्बन्धित विभागों के मंत्रियों से मार्गदर्शन भी लिया जाएगा। साथ ही, विभागों तथा महिलाओं के साथ संवाद भी स्थापित किया जाएगा। महिला जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी मिशन शक्ति में सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के साथ–साथ उनका फीडबैक भी लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप यूपी में कानून का राज स्थापित हुआ : मुख्यमंत्री

गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 207 करोड़ रुपये की लागत के उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया।

शिलान्यास कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि है। आजादी के आन्दोलन में लोकमान्य गंगाधर तिलक जी का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उनके सिद्धान्त तथा देशभक्ति के जज्बे को आने वाली पीढ़ियां ग्रहण कर देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। लोकमान्य तिलक के उद्घोष 'आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर रहूंगा' ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। उस समय लाल, बाल, पाल की त्रयी ने पूरे भारत में एक आन्दोलन खड़ा किया, जिससे हमारे देश का स्वतंत्रता मिली।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के नागरिकों में भय व्याप्त था और लोग पलायन करने को मजबूर थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार के गठन के बाद प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ। आज उत्तर प्रदेश देश में विकास की 44 योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने ने कहा कि योजना बनाना बड़ा सरल होता है, लेकिन इन योजनाओं को भूमि पर उतारना, बिचौलियों को खत्म करना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट व रिश्वत के योजना का लाभ मिल सके, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। लेकिन मुख्यमंत्री व उनकी टीम ने ऐसा करके दिखलाया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया है। चाहे औद्योगिक निवेश हो या योजनाओं का सफल क्रियान्वयन, कानून–व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो या गरीब किसान की ऋण माफी, हर घर में शौचालय बनाना तथा घर विहीन को घर देने का कार्य उत्तर प्रदेश में किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 01 करोड़ 47 लाख महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने के साथ ही इतने घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य हो रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 04 वर्ष में ही 11 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था 22 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बन गयी है, जो देश में दूसरे नम्बर की अर्थव्यवस्था है। कोविड–19 की दोनों लहरों में उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी अच्छा कार्य किया है। वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, बेड की संख्या बढ़ाने तथा कोविड से सुरक्षा प्रदान करने में प्रदेश देश में सबसे आगे है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र व राज्य सरकार पूरी संवेदना के साथ जनहित के कार्य कर रही हैं। इस स्थान पर एक विशाल संकुल बनेगा, जिसका बीजारोपण आज हुआ है। जब यह एक वट वृक्ष बनेगा तो अनेक बच्चे यहां से अपना कैरियर बनाएंगे। अनेक बच्चे यहां पर अनुसंधान में हिस्सा लेकर न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश की कानून–व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने का कार्य करेंगे।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रुप में कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने विश्व में अपनी तरह की सबसे पहली फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी बनाने का कार्य किया था। वर्ष 2019 में गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी।

उन्होंने कहा कि उ प्र स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज 207 करोड़ रुपये खर्च करके बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने यहां पर 15 करोड़ रुपये की धनराशि से सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स इन डीएनए का अनुमोदन किया है। यह सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा। डीएनए परीक्षण के क्षेत्र में यह अद्वितीय संस्थान होगा। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री ने पूरे देश की कानून–व्यवस्था को बल देने की शुरुआत की है।

मीडिया समाज के सजग प्रहरी के रूप में सरकार का ध्यान ज्वलन्त मुद्दों की ओर दिलाता है : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मीडिया समाज के सजग प्रहरी के रूप में सरकार का ध्यान ज्वलन्त मुद्दों की ओर दिलाता है। मीडिया जगत द्वारा सही तथ्यों को रखने तथा सही समाचार देने से सरकार को समस्याओं के समाधान तथा रणनीति बनाने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मीडिया से प्राप्त होने वाले समाचारों से राज्य सरकार को कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाने में सहायता मिली।

मुख्यमंत्री लोक भवन सभागार में कोविड–19 संक्रमण के कारण दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को आर्थिक सहायता धनराशि के वितरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कोविड–19 संक्रमण के कारण दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को आर्थिक सहायता धनराशि का वितरण किया गया। कोरोना के कारण दिवंगत प्रत्येक पत्रकार के आश्रित को 10 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गयी। कुल 50 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को आर्थिक सहायता धनराशि दी गयी। कार्यक्रम के दौरान 02 मिनट का मौन रखकर दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण देश को अनेक लोगों को खोना पड़ा। इनमें राजनेता, नौकरशाह, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त लोग भी शामिल हैं। पीड़ित व्यक्ति के साथ जब सरकार और समाज खड़ा होता है, तो उसे चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सम्बल प्राप्त होता है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से पीड़ित परिवारों का सम्बल बनने का प्रयास किया है। संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' लागू की गयी है। निराश्रित महिलाओं के लिए भी एक नयी योजना लायी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 16–17 महीनों से पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी से जूझ रही है। इस महामारी के सामने विश्व की बड़ी–बड़ी ताकतें पस्त हुईं हैं। हर तबका इससे प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन के दौरान अधिसंख्य आबादी अपने घरों के अन्दर सुरक्षित थी। ऐसे में मीडिया कर्मी लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे थे। इससे उनके कोरोना से संक्रमित होने की आशंका निरन्तर बनी रहती थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन तथा वैज्ञानिकों के निरन्तर प्रयास से कोरोना के आने के 09 महीने में देश में 02 वैक्सीन तैयार हो गयी। हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन का सुरक्षा कवच दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं इण्डिया टीवी के मुख्य सम्पादक रजत शर्मा के मीडिया कर्मियों को भी वैक्सीन का सुरक्षा कवच दिलाने के लिए विशेष अभियान संचालित किये जाने के सुझाव के लिए आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा और लखनऊ में मीडिया कर्मियों के कोरोना वैक्सीनेशन के लिए विशेष वैक्सीनेशन सेण्टर स्थापित किये गये। इनके माध्यम से 25 हजार मीडिया कर्मियों एवं उनके परिजनों को वैक्सीन की खुराक दी गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन में वेस्टेज पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा जानकारी दी गयी कि प्रायः 01 वायल वैक्सीन से 10 लोगों का वैक्सीनेशन कराया जाता है, जबकि कोविशील्ड वैक्सीन के एक वायल से 11 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सकता है। इसके कुछ समय पश्चात उनके (मुख्यमंत्री) के द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय में संचालित वैक्सीनेशन सेण्टर का निरीक्षण किया गया, जहां एक वायल से 11 लोगों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा था। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में भी मीडिया ने रास्ता दिखाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन वर्तमान समय की व्यापक जरूरत है। यह कोरोना के संक्रमण के प्रति एक सुरक्षा कवच है। कुछ वैक्सीनेटेड लोगों में भी संक्रमण देखने में आया है, किन्तु ऐसे मामलों में यह माइल्ड था। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण तीव्र था। ऐसे में हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स का वैक्सीनेशन उपयोगी सिद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वैक्सीन पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम निर्बाध ढंग से चल रहा है। इससे लोगों को सुरक्षा मिलेगी।

वर्तमान सरकार ने सवा चार वर्षों के दौरान निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा व मार्गदर्शन से वर्तमान सरकार ने सवा चार वर्षों के दौरान निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। प्रदेश में चयन की प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। विगत सवा चार वर्षों के दौरान साढ़े चार लाख सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री लोक भवन में उ प्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्यधीनस्थ सेवा परीक्षा–2019 में चयनित उप जिलाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने 10 नवचयनित उप जिलाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने देश के सबसे बड़े राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था का भाग बनने के लिए नव चयनित उप जिलाधिकारियों को बधाई दी एवं उ प्र लोक सेवा आयोग को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से चयन प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उप्र लोक सेवा आयोग द्वारा जिस शुचिता के साथ उप जिलाधिकारियों का चयन किया गया है, उसी शुचिता के साथ नव चयनित उप जिलाधिकारी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन, निष्पक्षता व पारदर्शिता से करें, जिससे उनकी प्रशासनिक सेवाओं का लाभ प्रदेश के हर नागरिक को प्राप्त हो सके।

नवनियुक्त उप जिलाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा की रीढ़ माना जाता है। हर एक व्यक्ति को न्याय देना अधिकारियों का दायित्व होना चाहिए। अधिकारियों का यह ध्येय होना चाहिए है कि प्रत्येक पीड़ित को न्याय मिले तथा वह व्यक्ति इसका एहसास भी कर सके। प्रत्येक अधिकारी द्वारा समयबद्ध ढंग से जनता की समस्याओं की सुनवायी कर उसे न्याय दिए जाने से आमजन की बहुत सी समस्याओं का निस्तारण किया जा सकता है। हमें समाज की समस्याओं को सुलझाने का माध्यम बनना होगा। एक बेहतर संवाद के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक भी चयन प्रक्रिया न्यायालय में लम्बित नहीं है। पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी व निष्पक्षता के साथ सम्पूर्ण कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया। सभी बोर्डों और आयोगों से आग्रह किया गया कि पूरी ईमानदारी के साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। योग्यता, मेरिट और आरक्षण के नियमों का पूरा पालन करें। किसी भी प्रकार से, किसी भी बाहरी व्यक्ति को आपकी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। प्रदेश के युवाओं को उनकी प्रतिभा, क्षमता और योग्यता के अनुरूप, उनका स्थान प्राप्त होना ही चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पूर्व प्रदेश में सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया कलंकित हो चुकी थी। भाई–भतीजावाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार के कारण न्यायालय को जांच के आदेश देने पड़े थे। यह प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ था। पिछली सरकारों द्वारा कुत्सित मंशा के तहत युवाओं को कुंठित किया जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की अधिकतर समस्याएं राजस्व से जुड़ी होती हैं। आपराधिक गतिविधियों के पीछे भी ज्यादातर राजस्व विवाद ही होते हैं। राजस्व सम्बन्धी विवाद का समय से निस्तारण न हो पाने से आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, न्याय से कोई वंचित न रह पाए, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसलिए अधिकारियों को पूरी ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अपने–पराये का भेद किए बगैर, अपने पूरे ज्ञान, दक्षता और व्यवहार से हर एक व्यक्ति को सम्मान और न्याय दें। यह कार्य पद्धति से झलकना भी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद वे प्रतिदिन जनता दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से जनता से जरूर मिलते हैं। विगत 15–16 माह से कोरोना कालखण्ड में पीक के दौरान यह प्रभावित अवश्य हुआ, तब जनता दर्शन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था।

02 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय

- उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव अनुमोदित, मंत्रिपरिषद ने उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

- होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवावधि में (अधिवर्षता से पूर्व) मृत्यु की दशा में उनके नॉमिनी/उत्तराधिकारी को अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में उनको 5 लाख रू की अनुग्रह राशि दिये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।

- राज्य विधान मण्डल का आगामी सत्र 17 अगस्त, 2021 से मंत्रिपरिषद ने राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों का वर्ष 2021 का द्वितीय सत्र (वर्षाकालीन सत्र) दिनांक 17 अगस्त, 2021 (मंगलवार) को आहूत कर लिये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

- उप्र निरस्त अध्यादेश, 2021 का प्रारूप स्वीकृत, मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश निरस्त अध्यादेश, 2021 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ज्ञातव्य है कि कुल 312 अधिनियमों को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों से अनापत्तियां प्राप्त हुई, जिन्हें वर्तमान में अप्रचलित एवं अनुपयोगी होने के दृष्टिगत निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक शिशिर, आईएएस द्वारा प्रकाशित
प्रभारी सम्पादक : डॉ. सीमा गुप्ता